बंगलदेश के उदय से २०१२ तक के शासन काल का इतिहास: एक राजनैतिक शासन

अनुपम कुमारी, अनुसन्धान विद्वान्, राजनीति विज्ञान विभाग, औ पी जे एस यूनिवर्सिटी, चूरू (राजस्थान)
डॉ दीपक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, औ पी जे एस यूनिवर्सिटी, चूरू (राजस्थान)

मुजीब का दौर 1972 से 1975 तक चला,

पाकिस्तानी सेना के समर्पण के बाद, बांग्लादेशी सरकार ने अपनी राजधानी को कलकत्ता से ढाका स्थानांतरित कर दिया, जहां वह पाकिस्तान की एक जेल से शेख मुजीब की रिहाई की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप, उनके लिए बांग्लादेश के युद्ध के बाद के आर्थिक पुनर्निर्माण के साथ-साथ अपने देश के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भारत पर भरोसा करना स्वाभाविक ही था। जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और देश की आजादी का विरोध करने वाले अन्य संगठनों के कई अनियमित बैंडों के खिलाफ राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए उन्हें भारत से सहायता की भी आवश्यकता थी।3

हालाँकि जिस समय मुजीब बांग्लादेश में सत्ता में थे, उस समय को भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण संबंधों का स्वर्ण युग माना जा सकता है, फिर भी दोनों देशों को एक-दूसरे के द्वारा देखे जाने के तरीकों में अंतर था। 9 जनवरी, 1972 को मुजीब को भुट्टो द्वारा पाकिस्तान की जेल से मुक्त किए जाने और बांग्लादेश लौटने की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद, उन्होंने भारत के एक विमान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसके बजाय लंदन से नई दिल्ली होते हुए एक ब्रिटिश विमान से यात्रा करने का विकल्प चुना। ढाका के लिए। भुट्टो द्वारा मुजीब को पाकिस्तान की जेल से रिहा किए जाने के कुछ ही समय बाद यह हुआ। मुजीब का मानना है कि इस प्रस्ताव को ठुकराना ही विवेकपूर्ण काम था, इस तथ्य के बावजूद कि इससे नई दिल्ली को कुछ चोटिल भावनाओं का अनुभव हुआ होगा। वह किसी भारतीय विमान में ढाका वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि इससे यह आभास हो सकता था कि वह "भारत के प्रभाव में" था। उनका निर्णय इस तथ्य से भी जुड़ा था कि उनका ब्रिटेन के साथ स्वायत्त संबंध बनाने का इरादा था, वह राष्ट्र जिसने पूर्व में अपने औपनिवेशिक युग में इस क्षेत्र पर शासन किया था।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि मुजीब अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रदान की गई सभी सहायता के लिए भारत के प्रति आभारी नहीं थे। उन्होंने दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान "बांग्लादेश को अंधेरे से प्रकाश की ओर, कैद से आजादी की ओर, और उजाड़ से उम्मीद की ओर यात्रा करने में मदद करने के लिए" भारतीय लोगों और प्रशासन की ईमानदारी से प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा, "मुझे यह भी पता है कि भारत के लोग बहुत अमीर नहीं हैं। इसके बावजूद, उन्होंने हमारे लाखों लोगों को भोजन, आश्रय और समर्थन दिया- कुछ ऐसा जो केवल अपनी जरूरतों का त्याग करके ही किया जा सकता है। हम हमेशा रहेंगे भारतीय लोगों, भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार की दया, समझ और विचार के लिए आभारी हैं। हम इसे हमेशा याद रखेंगे। मेरे देश के लोग इस दौरान भारत की जनता और सरकार की सहायता के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।

उसके बाद, भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान, जो 6 फरवरी से 8 फरवरी, 1972 तक हुई, मुजीब ने श्रीमती गांधी के साथ कलकत्ता में एक बड़ी सभा के सामने इन विचारों पुष्टि की हैं , मुजीब के अनुसार, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी सिद्धांत उनकी मातृभूमि, बांग्लादेश और भारत द्वारा साझा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दोनों देशों के बीच "शाश्वत मित्रता" का वादा किया। उन्होंने मित्रता और सहयोग, आर्थिक सहायता, और अन्य मामलों की संधि पर चर्चा के दौरान मार्च के महीने में श्रीमती गांधी को ढाका आने के लिए आमंत्रित किया और स्वीकार किया, स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए, मुजीब ने श्रीमती गांधी से कहा कि वे भारतीय सेना को एक वर्ष या कम से कम छह महीने के लिए बांग्लादेश में रहने की अनुमति दें । मुजीब के अनुरोध को श्रीमती गांधी की स्वीकृति नहीं मिली । उन्होंने जवाब दिया कि वह केवल तभी ढाका जाने में दिलचस्पी

लेंगी, जब सभी भारतीय सैनिक शहर छोड़ देंगे, सिवाय उस ब्रिगेड के जो चटगाँव पहाड़ी जिलों में संचलन कार्यों में लगी हुई थी। इसलिए एक इन्फैन्ट्री ब्रिगेड को संचालन के लिए पीछे रखा गया था। चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में भले ही मार्च के मध्य तक (श्रीमती गांधी के ढाका पहुंचने से बहुत पहले) सभी भारतीय सेनाएं वापस ले ली गई थीं। जुलाई 1972 में यह ब्रिगेड भी पीछे हट गई।

मुजीब ने यह भी सिफारिश की कि भारत के साथ मित्रता, मित्रता और सहयोग की एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाएं क्योंकि यह नए स्वतंत्र बांग्लादेश की सुरक्षा का समर्थन करेगा, जिस पर अभी भी पाकिस्तानी सेना के अवशेषों का शासन था और जिसे अभी तक चीन या पाकिस्तान द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। भले ही भारत प्रस्ताव पर सहमत हो गया था, लेकिन यह माना जाता था कि कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण करने और ऐसा करने के एक महीने के भीतर संधि पर हस्ताक्षर करने से आलोचना होगी और यहां तक कि संदेह भी पैदा होगा कि वह भारत के दबाव में पहले से स्थायी, प्रभावी संबंध बनाने के लिए दबाव में था। नई बांग्लादेशी सरकार स्थिर हो गई थी और उसके पास सभी लाभों और कमियों को तौलने का मौका था।

1972 में 17 मार्च को, जब श्रीमती गांधी ढाका की राजकीय यात्रा पर थीं, उन्होंने भी इनसे काफी मिलते-जुलते विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने भाषण में मुक्ति बाहिनी को बहादुरी की कहानी, सच्चाई की लौ और न्याय की लौ के रूप में संदर्भित किया। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पच्चीस वर्षों के लिए वैध है और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा प्रेरित किया गया था जब उन्होंने दिल्ली में पहले एक दूसरे से अपनी अमर मित्रता व्यक्त की थी।

मुजीब और इंदिरा गांधी सत्ता में रहने के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच ठोस और लंबे समय तक चलने वाले सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव रखने के लिए जिम्मेदार थे। दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सद्भावना 1972 के व्यापार समझौते और दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विस्तार में परिलक्षित हुई थी। इन विकासों को दोनों देशों के नेताओं के बीच मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा उजागर किया गया था।

1972 और 1975 के बीच, मुजीब ने कई पाकिस्तानी समर्थक व्यक्तियों का पुनर्वास किया जो सशस्त्र बलों और प्रशासन के भीतर प्राधिकरण के पदों पर कार्यरत थे। इसके अलावा, उन्होंने जमात-ए-इस्लामी संगठन को माफी दी, जिसने पहले बांग्लादेश की स्थापना का विरोध किया था। अति-वामपंथी समूह, जो चीनी समर्थक थे और गरीब जनता को एक चीनी मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, मुजीब सरकार के लिए भी एक चुनौती थी। यह खतरा इस तथ्य से बढ़ गया था कि मुजीब सरकार पहले से ही अन्य तत्वों से खतरे में थी ।

ये तत्व पाकिस्तानी सेना के लिए काम करने वाले कठपुतली थे, और वे मुक्ति-विरोधी थे और सच में, बांग्लादेशी-विरोधी भी थे । उन्हें भारत विरोधी मुद्रा अपनाकर अपनी नीतियों को विकसित करने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने मुजीब की उदारता और उदारता का अनुचित लाभ उठाया और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए किया। उन्होंने मित्रता संधि की मंशा पर सवाल उठाया और इस आधार पर इसका विरोध किया कि यह 1971 की भारत-यूएसएसआर मित्रता संधि की प्रतिकृति थी, जो भारत के लिए बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दावा किया कि संधि संधि की प्रतिकृति थी । उन्होंने यह अफवाह भी फैलाई कि भारत ने 1971 का युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में विभाजित करने के अपने रणनीतिक लक्ष्य के लिए लड़ा था । यह दावा इस विचार पर आधारित था कि भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करना चाहता है । उन्होंने तर्क दिया कि नई दिल्ली एक क्षेत्रीय महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी और एक आधिपत्य वाला देश था, और पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति उसके लिए क्षेत्रीय महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए काम आई। उन्हें सोवियत संघ के बारे में भी गंभीर गलतफहमी थी, जिसने मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के पाकिस्तान के प्रयासों के बजाय बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो शक्ति का लगातार इस्तेमाल किया था।

कई मुक्ति बाहिनी योद्धाओं ने इस भावना को साझा किया कि भारतीय सशस्त्र बलों को मुक्ति संग्राम में उनकी भूमिका के लिए अनुचित रूप से अत्यधिक प्रशंसा मिल रही थी। उनका विश्वास था कि मुक्ति बाहिनी युद्ध जीतने में सफल रही थी; भारतीय सेना ने देश भर में चहलकदमी की और ढाका में आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना पर कब्जा करने वाली सेना होने का आरोप लगाया गया था जो हथियारों और नागरिक संपत्ति को चुराने और उन्हें भारत वापस लाने में लगी हुई थी। इस आरोप के कारण भारतीय सेना को कब्जे वाली सेना कहा जाने लगा। हालाँकि, मुजीब ने कलकत्ता में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ "पकड़े गए हथियारों की वापसी" का मुद्दा उठाया और इसके परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ हथियार बांग्लादेश पहुंचा दिए गए। इन और अन्य भारत विरोधी समस्याओं को मीडिया और बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले तत्वों द्वारा अक्सर उठाया गया था।

मुजीब ने एक विशेष बल राखी वाहिनी की स्थापना की, आपातकाल की स्थिति घोषित की, सोवियत मॉडल, बक्सल के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सभी अधिकारियों को अपने हाथों में केंद्रीकृत किया। इसके अलावा, वह सेना के आकार को छोटा करने के बारे में सोच रहा था, जो कि नियमित सैनिकों की सराहना नहीं थी। हालाँकि ऐसे उदाहरण थे जब उनकी राजनीतिक चालें भारत की राजनीतिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं थीं, फिर भी नई दिल्ली ने उन्हें बांग्लादेश की आंतरिक चिंता माना, इस तथ्य के बावजूद कि वे बांग्लादेशी क्षेत्र में घटित हुईं। उस समय की अवधि के दौरान, भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी राजनीतिक कठिनाइयों का सामना कर रही थीं, जिसने उन्हें आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए प्रेरित किया।

मुजीब द्वारा भारत के प्रति किए गए हर दोस्ताना भाव की व्याख्या उनके विरोधी द्वारा "भारतीय शिविर में गिरने या भारत की ओर बहुत अधिक झुकाव" के रूप में की गई थी और इनमें से प्रत्येक इशारे पर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी। 15 अगस्त, 1975 को ढाका में मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या के बाद यह मामला सामने आया (उस समय दो बेटियों को छोड़कर, जो देश से बाहर यात्रा कर रही थीं)। हत्यारे बांग्लादेशी सेना के सदस्य थे जो असंतुष्ट थे और गलत सूचना दे रहे थे।

शुरुआत में, केवल भारत, सोवियत संघ और भूटान ने ही बांग्लादेश को मान्यता दी थी; नतीजतन, आर्थिक सहायता या तो विश्व संगठनों या अन्य देशों से नहीं आ रही थी, विशेष रूप से वे देश जो पाकिस्तान समर्थक थे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और मध्य पूर्व के देश। भूटान ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) पर भी अधिकार कर लिया, जिसने न केवल इस्लामिक दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ एक धार्मिक संबंध साझा किया बल्कि बांग्लादेश की सहायता के लिए तेल आपूर्ति और वित्तीय साधनों पर नियंत्रण भी रखा।

1977 से 1981: उपरोक्त अवधि के दौरान ज़िया का युग

1977 में, जब जिया सरकार ने देश में राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और देसाई सरकार भी निकट पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में विदेश नीति को नई दिशा देने में सक्षम थी, गंगा जल के बंटवारे पर 5 नवंबर, 1977 को एक समझौता हुआ। मंदी के मौसम के दौरान, यह समझौता आपसी भरोसे और भरोसे पर आधारित एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने की दिशा में एक बड़ा और बहुत ही सकारात्मक कदम था। गंगा जल समझौता 1977: इस विशेष अवधि (1975-1990) की सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा जल समझौता 1977 थी। उस समय दोनों देशों में कुछ परेशानियों और बहुत ही परेशान करने वाली घरेलू परिस्थितियों के बावजूद समझौता किया गया था। जनता सरकार, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार ने केंद्र में मार्च 1977 के अंतिम सप्ताह में सत्ता संभाली। नई सरकार ने "फायदेमंद द्विपक्षीयवाद" के तहत पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों की नीति अपनाई। बांग्लादेश के साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी उत्सुकता में, जनता सरकार ने फरक्का और अन्य मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी । 13 1977 के समझौते से पहले दोनों के नेताओं के बीच आधिकारिक स्तर की

वार्ता के तीन दौर हुए थे। 20 से 30 सितंबर, 1977 तक आयोजित देशों। समझौते पर अंततः बातचीत हुई और ढाका में भारत गणराज्य की सरकार के लिए श्री सुरजीत सिंह बुरनाला और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट के लिए रियर एडमिरल मुशर्रफ हुसैन खान द्वारा मंत्री स्तर पर हस्ताक्षर किए गए।

अवधि 1982 से 1991: इरशाद काल

इरशाद अवधि पहली बार 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधान मंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी से मेल खाती है, जब वह पद पर रहते हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 24 जुलाई 1989 तक श्री राजीव गांधी और बाद में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, और फिर श्री चंद्रशेखर जिन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। इरशाद के पास बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और विदेशी संबंधों को निर्देशित करने के लिए शुरू में कम से कम स्वतंत्र हाथ था। विपक्षी पार्टियां एक नहीं थीं और उनका मुंह बंद कर दिया गया था, अंतर-सैन्य संघर्ष ठंडे बस्ते में था, और भारत सरकार ने बांग्लादेश के नेतृत्व के उनके कब्जे को समभाव के साथ स्वीकार किया। ज़िउर रहमान द्वारा सामना की गई अधिक अप्रत्याशित स्थिति की तुलना में सत्ता हासिल करने पर इरशाद की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति, जिस तरह से इरशाद और भारत सरकार ने कुछ अधिक प्रमुख मुद्दों पर अपनी बातचीत शुरू की, उनके बीच लंबे समय से स्थायी और उभर रहे थे। संबंधित राज्यों, इरशाद और भारत सरकार के बीच एक स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध का आश्वासन दिया गया।

1982 भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों के लिए "हनीमून ईयर" जैसा था। बाद के वर्षों की घरेलू राजनीतिक अशांति की व्यस्त मांगों में न तो इरशाद और न ही श्रीमती गांधी अभी तक बहुत अधिक उलझी हुई थीं। जबकि इरशाद आश्वासन दे रहे थे कि उनकी सरकार की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देगी, श्रीमती गांधी के पास भारत-बांग्लादेश संबंधों में किसी भी संभावित बदलाव के बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। बांग्लादेश में एक सौहार्दपूर्ण शासन का अस्तित्व, एक असंबद्ध भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से दोनों राज्यों के बीच सुचारू संबंधों के लिए सर्वोत्तम आशा प्रदान करता प्रतीत होता है।16

अवधि 1992-1996: बेगम खालिदा जिया का पहला कार्यकाल

इस अवधि के दौरान, श्री पी.वी.नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधान मंत्री थे, उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक छोटी अवधि के लिए, फिर जून 1996 से अप्रैल 1997 तक श्री हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा और अंत में, अप्रैल से श्री इंद्र कुमार गुजराल 1997 से मार्च 1998 तक।

अयोध्या की बाबरी मस्जिद भारतीय राजनीतिक विमर्श पर हावी थी। 6 दिसंबर, 1992 हमारी धर्मनिरपेक्ष परंपरा का एक काला दिन था जब कुछ हजार कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और राज्य और केंद्र सरकारें इसकी रक्षा करने में विफल रहीं। भारत की सड़कों और गलियों में, एक विश्वासघाती लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया, बसों पर हमला किया गया और जला दिया गया, इमारतों को जमीन पर गिरा दिया गया, प्रदर्शनकारी मारे गए, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया और खून की गंध हवा में भर गई। मस्जिद का विध्वंस कोई दुर्घटना नहीं थी; यह बहुत सावधानी से योजना बनाई गई थी,

अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां घटनास्थल की ओर जा रही थीं, लेकिन कारसेवकों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जब अर्धसैनिक बलों ने स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से सड़क को खाली करने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति मांगी तो इससे इनकार कर दिया गया। वहां कोई पुलिस नहीं थी, वहां कोई अर्धसैनिक बल नहीं था और मीडिया को बाहर खदेड़ दिया गया था। कारसेवकों का पूरा नियंत्रण था। दोपहर होते-होते पूरे भारत में दंगे भड़क उठे और सड़कों पर खून बहने लगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेताओं के

खिलाफ धारा 153ए आईपीसी के तहत साम्प्रदायिक नफरत भड़काने और शांति भंग करने का मामला दर्ज किया था.

बेगम खालिदा जिया ने भी चीन के साथ संबंधों को मजबूत करके अपने दिवंगत पति की नीतियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, उम्मीद है कि यह भारत के खिलाफ प्रति-संतुलन के रूप में काम करेगा। दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप, उनकी सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को नियंत्रित नहीं किया। उसने सार्क में भी द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। हालाँकि, द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में आ रहे थे, और सत्यापन के बाद उन्हें वापस लेने पर सहमत हुए।

यह देखते हुए कि सार्क द्विपक्षीय या क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने में प्रभावी नहीं था, उसने अक्टूबर 1993 में गंगा जल मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी फैसला किया, लेकिन कोई नई दिशा प्राप्त करने में विफल रही क्योंकि महासभा ने अपने पहले के रुख को अपनाया। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप भारत की स्थिति कठोर हो गई, चूंकि अक्टूबर में बेगम जिया के सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर कई हमले हुए थे, भारत उनकी रक्षा के लिए ढाका के साथ मामला उठाने के लिए विवश था। 23 प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के विशेष दूत श्री बृजेश मिश्रा को आश्वासन दिया। प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी कि वह सुनिश्चित करेंगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाए। उन्होंने सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने की इच्छा भी व्यक्त की, 1995 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान, बांग्लादेश में आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में, बेगम ज़िया ने नदी के पानी के बंटवारे पर एक कठोर रुख अपनाया। हालांकि उनके दो मंत्रियों द्वारा सलाह दी गई थी कि यह सौदा बांग्लादेश के लाभ के लिए था, उन्होंने अपना रुख नहीं बदला और इसलिए नरसिम्हा राव सरकार के साथ गंगा जल पर एक संधि पर हस्ताक्षर करने का अवसर खो दिया।

1996-2001 की अवधि: बेगम शेख हसीना का पहला कार्यकाल

1996 से 1997 तक की इस अवधि में, श्री देवेगौड़ा शुरू में प्रधान मंत्री थे और बाद में, श्री आई के गुजराल ने उनसे पदभार संभाला। श्री वाजपेयी 1998 से 2004 तक प्रधान मंत्री थे, बेगम शेख हसीना के युग के दौरान, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध आगे बढ़े और बेहतर हुए, हालांकि एकतरफा - केवल भारत की ओर से। जैसा कि वह भी एक गठबंधन का नेतृत्व कर रही थीं, वह संभवतः कठोर निर्णय नहीं ले सकती थीं और भारत विरोधी भावनाओं का मुकाबला नहीं कर सकती थीं, जो 1975 से उनके विरोधियों द्वारा फैलाई गई थीं। देवागौड़ा और शेख हसीना दोनों प्रधानमंत्रियों ने बड़ी दूरदर्शिता, एक बहुत उच्च क्रम के नेतृत्व और नेतृत्व का परिचय दिया। गंगा नदी के जल को साझा करने पर सहमत होकर दूरदर्शिता। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1996 तक अपनी भारत यात्रा के दौरान, शेख हसीना ने 30 साल की अवधि के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। श्री आई के गुजराल, विदेश मंत्री द्वारा बहुत ही कुशलता से बातचीत की गई, संधि द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर बन गई और यह साबित कर दिया कि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए किसी तीसरी शक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं है। यह संधि 13 वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है और भारत ने धार्मिक रूप से कम अवधि के दौरान फरक्का से बांग्लादेश को अनुरोध किए गए पानी को छोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान किया है, जो बांग्लादेश और उसके पड़ोसियों के प्रति भारत की सद्भावना का प्रमाण है की यदि बांग्लादेश द्वारा कोई हो, पर उचित विचार किया जाता है और पारस्परिक संतुष्टि के लिए बातचीत द्वारा हल किया जाता है।

अवधि 2002-2006: बेगम खालिदा जिया का दूसरा कार्यकाल

उपरोक्त अवधि के दौरान, श्री वाजपेयी ने 2004 तक भारत में सरकार का नेतृत्व किया, जिसके बाद डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, बेगम जिया

की बीएनपी के नेतृत्व वाली चार पार्टी गठबंधनों (कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक जमात सहित) ने चुनाव जीता प्रचंड बहुमत, 283 सीटों में से 202 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव संबंधी हिंसा में लगभग 300 लोग मारे गए, जिनमें अवामी लीग के समर्थक माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी शामिल थे। अवामी लीग, जिसे बांग्लादेश में "भारत समर्थक" के रूप में माना जाता है, ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, केवल 62 सीटें जीतीं। इरशाद की पार्टी केवल 14 में कामयाब रही और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुनवाई के डर से उन्होंने देश छोड़ दिया।

चुनाव प्रचार के दौरान, जमात के छात्र समूहों ने तालिबान की शपथ ली और अक्सर बांग्लादेश को अफगानिस्तान में बदलने के नारे लगाए। पिरोजपुर से चुनाव लड़ने वाले उनके वरिष्ठ नेता मौलाना सईदी ने अपने प्रतिद्वंद्वी हैदर (अवामी लीग के एक सम्मानित सदस्य) को "हिंदू काफिर" भी कहा। हालाँकि मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान को उनके खुले समर्थन और पाकिस्तान के साथ सहयोग के कारण उन्हें "रजाकार" होने का कलंक लगा था, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर इसे सम्मान के बिल्ला के रूप में दिखाया। उन्होंने मुसलमानों से "एक हिंदू काफ़िर की तुलना में एक मुस्लिम रज़ाकार को वोट देने" की अपील की, और जीत हासिल की। इन बयानों ने बेगम जिया के दूसरे शासन के तहत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इस्लामिक राज्य बनने की चिंता जताई।26

कार्यभार संभालने पर, बेगम ज़िया ने कहा कि धर्म उनके प्रशासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, फलस्वरूप उन्होंने बांग्लादेश के इस्लामिक राज्य बनने की आशंकाओं को दूर कर दिया। प्रधान मंत्री वाजपेयी ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने ढाका के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की इच्छा व्यक्त की। यह आशा की गई थी कि गंगा जल संधि के बाद शेख हसीना द्वारा बनाई गई सद्भावना पर बेगम जिया का निर्माण होगा। नई दिल्ली को उम्मीद थी कि बेगम जिया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पारगमन अधिकारों के बारे में भारत की चिंताओं और बांग्लादेश की धरती से संचालित होने वाले भारतीय विद्रोही समूहों के संबंध में सुरक्षा चिंता की सराहना करेंगी।

हालाँकि, अपने पहले के कार्यकाल के अनुभव के साथ ही, बेगम ज़िया ने भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना जारी रखा। अगस्त 2005 में बिम्सटेक के मौके पर डॉ मनमोहन सिंह के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को अतीत की कलह के लिए बंधक नहीं बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बेगम जिया ने भारत के प्रधान मंत्री से वादा किया कि वह नई दिल्ली की झरझरा सीमा के माध्यम से बांग्लादेशियों के निरंतर प्रवाह और उनके देश में भारत विरोधी विद्रोही समूहों के शिविरों के तेजी से बढ़ने की शिकायतों पर नए सिरे से विचार करेगी।

17 अगस्त 2005 को बांग्लादेश के 64 जिलों में से 63 में लगभग एक साथ हुए बम विस्फोटों के तुरंत बाद, जिसमें विपक्ष की नेता शेख हसीना चमत्कारिक ढंग से बच निकलीं, बांग्लादेश ने भारत की ओर आरोप लगाने वाली उंगली उठाई। दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई, जब 20 सितंबर 2005 को बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री मोरशेड खान ने बांग्लादेश विरोधी उग्रवादियों को शरण देने के लिए भारत पर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि 17 अगस्त के घातक बम विस्फोटों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। भारत से आयात बंद करने और इसकी विदेशी मुद्रा आय को 300 अमेरिकी डॉलर तक "नष्ट" करने की धमकी के अलावा, उन्होंने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों पड़ोसी बांग्लादेश के "तालाबंदी" की खुली धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि "भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश से घिरे हुए हैं

ढाका ने भारत को म्यांमार से अनुबंधित गैस के हस्तांतरण के लिए अपने क्षेत्र के माध्यम से एक पाइपलाइन का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, मिजोरम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ व्यापार के लिए चटगाँव बंदरगाह के उपयोग की अनुमति देने के लिए नई दिल्ली के अनुरोध पर सहमति नहीं हुई। इसने भारत को बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए

म्यांमार में स्वेट बंदरगाह विकसित करने के लिए म्यांमार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

प्रधान मंत्री, बेगम जिया ने भी ढाका चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए कहा कि रॉ ने उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हमलों को अंजाम दिया हो सकता है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच दो खूनी झड़पें हुईं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। फिर भी, स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत कर जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। नकारात्मक वाइब्स के बावजूद, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त, राजदूत श्रीमती वीना सीकरी की पहल पर, स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह को उनके जीवनसाथी के साथ 16 दिसंबर 2005 को मुख्यालय पूर्वी कमान में विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। , कोलकाता, तब से इसे एक वार्षिक विशेषता के रूप में संस्थागत कर दिया गया है।

2007-2008 से संबंध: केयर टेकर सरकार द्वारा नियम

1971 के युद्ध के भारतीय युद्ध दिग्गजों के एक समूह और उनकी पत्नियों को एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय दिवस, 26 मार्च 2008 के दौरान राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2007 में, भारत ने पारस्परिकता में कुछ भी मांगे बिना, भूमि और एन्क्लेव मुद्दे को हल करने के लिए एक समग्र प्रस्ताव दिया। हालांकि, ढाका से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। भारत ने बांग्लादेश द्वारा वांछित दस अपराधियों को सौंप दिया, जबकि ढाका ने बदले में दस उल्फा सदस्यों को सौंप दिया, हालांकि वे बहुत कम स्थिति के थे और कोई महत्व नहीं थे। ढाका अभी भी परेश बरुआ और अनूप चेटिया जैसे उल्फा के शीर्ष नेताओं का घर है, जिनके खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच संबंधों में सुधार दिखाई दिया। अधिकारियों की बैठकों के अलावा, दोनों पक्षों के परिवारों ने दोस्ताना माहौल में सीमा पार अनौपचारिक सभाओं से मुलाकात की। अगस्त 2008 में, भारत के महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल ने लगभग 150 विद्रोहियों की सूची और बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों के 30 शिविरों का विवरण अपने समकक्ष को सौंपा। हालांकि बांग्लादेश ने उन्हें ट्रैक करने, गिरफ्तार करने और उन्हें सौंपने पर सहमति व्यक्त की और यहां तक कि संयुक्त अभियान चलाने की इच्छा भी दिखाई, बांग्लादेश राइफल्स द्वारा अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाया गया है ।

2009 से 2012 की अवधि: शेख हसीना का शासन

बांग्लादेश की सेना ने देश पर शासन किया, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से एक कार्यवाहक सरकार की आड़ में, 2006 से 2008 तक। जैसा कि बाहर और अंदर के दबावों में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र में लौट आया, अंततः सेना ने भरोसा किया और 29 दिसंबर, 2008 को आम चुनाव हुए। अवामी पार्टी भारी जनादेश के साथ सत्ता में आई थी, हालांकि उसने चार पार्टियों के गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था। अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया था, जिस पर उनके टिके रहने की संभावना है। AL के नेतृत्व में 14 दलों के गठबंधन ने चुनावों में शानदार जीत हासिल की और जनवरी की शुरुआत में एक नई सरकार बनाई। प्रधान मंत्री के रूप में, शेख हसीना ने देश की विदेश नीति उन्मुखीकरण, विशेष रूप से इसकी भारत नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तेजी से कदम उठाए। बाद के तीन वर्षों के घटनाक्रम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हसीना सरकार ने अपने पूर्ववर्तियों की नीतियों को उलट दिया और भारत-सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। सैद्धांतिक रूप से, देश की भारत नीति पर निर्णय लेने के लिए उस समय सरकार के पास वैकल्पिक विकल्प थे। उदाहरण के लिए, यह अपने पूर्ववर्तियों की नीति के साथ जारी रह सकता था और भारत की कीमत पर चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रख सकता था; या यह एक 'तटस्थ' या 'संतुलित' दृष्टिकोण का विकल्प चुन सकता था, जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान/इस्लामी देशों को समान स्तर पर शामिल किया गया था। हसीना सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बढ़ती शक्ति के साथ भारत और बैंड वैगन के करीब आने का विकल्प चुना।

नई दिल्ली ने ढाका की भारत-सकारात्मक विदेश नीति का स्वागत किया और हसीना सरकार की ओर कई पहल करके सकारात्मक इशारों के माध्यम से अवसर को जब्त करने का प्रयास किया। कार्यभार संभालने के एक साल बाद, शेख हसीना जनवरी 2010 में अपने भारतीय समकक्ष से मिलने नई दिल्ली गईं। इस शिखर बैठक में, वे दोनों पड़ोसियों के बीच एक 'अपरिवर्तनीय' सहकारी संबंध बनाने के लिए एक अग्रगामी, परिवर्तनकारी एजेंडे पर सहमत हुए। 30 सितंबर 2011 में, भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने ढाका की वापसी की यात्रा की। 2010 में शुरू किए गए परिवर्तनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाएं। भले ही यह तथ्य है कि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, रिश्ते एक ऐसे स्तर पर बदल गए हैं जो पिछले कई दशकों में स्पष्ट नहीं थे।

संदर्भ

1. "103 पर, फ़र्स्ट-टाइमर एक सबक सीखता है: राशन कार्ड की तुलना में वोटर कार्ड प्राप्त करना आसान", द इंडियन एक्सप्रेस, 5 मई, 2016।
2. "पश्चिम बंगाल चुनाव: परिक्षेत्रों में, हम सरकार के लिए एक संख्या थे, अब हम सिर्फ मतदाता हैं", द इंडियन एक्सप्रेस, 5 मई, 2016।
3. अनासुआ बसु रे चौधरी और प्राणश्री बसु, "भारत-बांग्लादेश कनेक्टिविटी: संभावनाएं और चुनौतियां", ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 2 जून 2015।
4. "भारत, बांग्लादेश वीजा मंजूरी को आसान बनाने के लिए वाणिज्य दूतावासों को मजबूत करेगा", बिजनेस स्टैंडर्ड, 6 मई 2016।
5. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, "समझौतों की सूची, एमओयू और अन्य दस्तावेजों की सूची प्रधान मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान संपन्न हुई", विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, 6 जून 2015।
6. "बांग्लादेश की लापता लड़कियां", द हिंदू, 06 अप्रैल 2016।
7. "बांग्लादेश ने चिंता जताई क्योंकि राजनाथ के आदेश से गोमांस की आपूर्ति प्रभावित हुई", द इंडियन एक्सप्रेस, 1 दिसंबर 2015। उक्त।

SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY